

‘सिंधु जल समझौते से बचने वाला पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरु को मिलेगा’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुसाईंसर बड़ा में अंत्योदय के शिविर का अवलोकन किया

बीकानेर, 8 जुलाई (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से रह हुए सिंधु जल समझौते से बचने वाला पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरु को मिलने वाला है। ये चारों जिले बड़े सीमाव्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं, वो सभी पूरे होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता आए तो पूछना कि उनके वादों का क्या हुआ।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बीकानेर के गुंसाईंसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित किया। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ भी थे।

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन हम श्री डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करेंगे।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्रीडूंगरगढ़ के लिए जमीन देने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए जरूरी बजट भी दिया जायेगा। कांग्रेस ने जिस व्यापारी से घोषणा कराई थी, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन हम ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने व्यापारी पर दबाव बनाकर सिर्फ घोषणा करवा ली, अब वो टालमटोल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला नहीं होगा, तब तक राजस्थान उत्कृष्ट नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इंदिरा गांधी नहर के लिए चार हजार



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के गुंसाईंसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और सभा को संबोधित किया।

करोड़ रूपए दिए हैं और बीकानेर, चूरु, श्रीगंगानगर में इससे काम होगा। किसान को पानी-बिजली और बीज देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

विधायक ताराचंद सारस्वत ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री के समक्ष

ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग रखी तथा सरकारी कॉलेज की घोषणा करने की मांग की।

ताराचंद सारस्वत के भाषण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके विधायक होशियार हैं। दो मिनट का बोला था,

लेकिन पूरे तीन पन्ने का भाषण बोल दिया।

उन्होंने अपनी सभी मांगें रख दी हैं। जो काम अधूरे हैं, उनके बारे में भी बोल दिया और जो करवाने हैं, उनके बारे में भी बोल दिया।

उदयपुर फाइल्स फिल्म पर प्रतिबंध की माँग पर सुनवाई आज होगी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म और उसके ट्रेलर पर बैन लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है

कहानी हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच गंभीर दूरी और तनाव पैदा कर सकती है। याचिका की 9 जुलाई, बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

याचिका में कहा गया है, “फिल्म का ट्रेलर मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक तरीके से पेश करता है, जिससे उस समुदाय के लोगों के सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। फिल्म बहुत भड़काऊ है और दो समुदायों के बीच फूट डाल सकती है, जिससे देशभर में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है।

याचिका कहती है कि “ट्रेलर की सामग्री खास तौर पर मुस्लिम समुदाय

■ **यह फिल्म उदयपुर में दिन दहाड़े हुई कन्हैयालाल दर्जी की नृशंस हत्या पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि मुस्लिम कट्टरपंथी युवकों ने तलवारों से काट कर कन्हैयालाल की हत्या कर दी थी।**

■ **जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फिल्म से हिंदू-मुस्लिम वैमनस्यता को बढ़ावा मिलेगा और इससे देश भर में शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है।**

■ **फिल्म 11 जुलाई को रिलीज हो रही है।**

को निशाना बनाती दिखती है, जिसमें उनके बारे में गलत और तोड़ी-मरोड़ी गई बातें दिखाकर भाईचारे को तोड़ने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की

बिहार में 47 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा करवाए

नयी दिल्ली, 08 जुलाई। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में दो सप्ताह के अंदर चुनाव अधिकारियों को लगभग आधे मतदाताओं (47 प्रतिशत) के भरे हुए गणना-फार्म प्राप्त हो चुके हैं। यह जानकारी मंगलवार को आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्त में दी गयी। गणना-फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। आयोग ने कहा है कि बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 3,70,77,077 गणना फार्म मिल चुके हैं, जो राज्य में कुल 7,89,69,844 मतदाताओं की संख्या का 46.95 प्रतिशत है। आयोग ने पुनरीक्षण के लिए दिशानिर्देश गत 24 जून को जारी किए थे। आयोग ने पुनरीक्षण के काम के लिए इन दो सप्ताह में 7.90 करोड़ फॉर्म मुद्रित कराए हैं और सूची में दर्ज 97 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं (7,70,44,990) के गणना-फार्म वितरित किए जा चुके हैं। आयोग का कहना है कि अब तक 18.16 प्रतिशत फॉर्म उसके ऐप ईसीआईनेट पर अपलोड किए जा चुके हैं।

अश्वनी पंजाब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वहीं, अब भाजपा के संगठनात्मक ढाँचे को देखते हुए अश्वनी शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना रणनीतिक फैसला माना जा रहा है।

कांग्रेस ने माना कर्नाटक में पार्टी में अन्तर्कलह है

- **कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने कहा, कई विधायकों को पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से शिकायत है।**
- **लेकिन सुरजेवाला ने नेतृत्व परिवर्तन से इन्कार किया व कहा कि इस पर फैसला हाईकमान ही ले सकते हैं।**

मैंने उनसे कहा है कि वे ये सब मुझे लिखित में दें। हम उनका बारी बारी से हल निकालेंगे।

कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि राज्य में पार्टी में हालात का दबाव में हैं लेकिन आम चर्चा यह है कि शिकायतों के सामने आने से पार्टी की अंदरूनी कलह दिखने लगी है। अब सुरजेवाला ने जो रुख अपनाया है, वह बंद कمر में बातचीत

और मीडिया की निगाहों से दूर रहने का प्रयास है। उन्होंने समस्या के हल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है, जिससे लगता है कि पार्टी शिकायतों के निपटारे के मामले में कोई गंभीर कदम उठाने वाली नहीं है।

राज्य में नेतृत्व बदलाव को लेकर उठे सवालों को दरकिनार करते हुए, उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा, एक

12 अन्य देशों के नेताओं को भेजे गए,

जिनमें मलेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, लाओस, टय्नीसीया, इंडोनेशिया, बंगलादेश, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कंबोडिया, थाईलैंड शामिल हैं। उन्हें यह सूचना दी गई कि अगले महीने से उन पर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाएंगे। मलेशिया, कजाकिस्तान और टय्नीसीया पर टैरिफ दर 25 प्रतिशत होगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका और बिर्हाना के लिए यह 30 प्रतिशत होगी। इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत और बांग्लादेश एवं सर्बिया पर 35 प्रतिशत टैरिफ दर लागू होगी। कंबोडिया और थाईलैंड पर टैरिफ दर 36 प्रतिशत होगी, जबकि लाओस एवं म्यांमार पर यह 40 प्रतिशत तक होगी।

पत्रकार की संपादक बनने की आकांक्षा हो सकती है, लेकिन इस फैसले की डोर तो चैनल मालिक के हाथ में होती है। सुरजेवाला के बयान नेतृत्व संबंधी फैसलों पर कांग्रेस हाईकमान की मजबूत पकड़ को दिखाते हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर, सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि ये दौरे पूरी तरह से प्रशासनिक हैं। उन्होंने कहा, “वे सरकारी काम से दिल्ली जा रहे हैं—ताकि वे केन्द्र के समक्ष कर्नाटक के मसले रख सकें। यह उनका कर्तव्य है और वे इसे पूरा कर रहे हैं।”

रेल मंत्री अश्विनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वैष्णव समाज में परम्परा रही है कि घर के किसी व्योयुद्ध सदस्य का निधन होता है, तो बैकुंठी निकाली जाती है। अंतिम संस्कार भी पार्थिव देह को बैठाकर ही किया जाता है।

रेल मंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2021 को पहली बार अश्विनी वैष्णव जोधपुर आए थे। इस दौरान पिता-पुत्र की मुलाकात काफी कम समय के लिए हो पाई थी, तब दाऊलाल वैष्णव ने अश्विनी वैष्णव को एक चिट्ठी लिखी।

उन्होंने लिखा— कर्तव्य को इतनी निष्ठा से निष्पादित करो कि हर रेलयात्री का चेहरा यात्रा के दौरान फूल सा खिले।

स्व. दाऊलाल वैष्णव की अंतिम यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं सहित, शहर के लोग उपस्थित थे। अंतिम संस्कार के काग़ रमशान घाट पर सीएम भजनलाल शर्मा तथा भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ भी पहुंचे।

इज़रायल के प्र.मंत्री... ‘पुलवामा हमले के लिए विस्फोटक एमेज़ॉन से खरीदे गए थे’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तनाव कम कराने तथा सर्बिया और कोसोवो के बीच समझौता कराने में उनके प्रयासों को अन्देखा किया। हालांकि भारत ने अधिकारिक रूप से पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष में ट्रंप की भूमिका का खंडन किया है और कहा है कि आपसी बातचीत से समाधान हुआ।

ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मिश्र, बर्मा, इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने में मदद की है, और अब्राहम समझौते (अब्राहम आई) के जरिए इज़राइल और कुछ अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने में भी उनकी भूमिका रही है।

ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में

खुद को एक शांति निर्माता बताया था और वादा किया था कि वे अपने बातचीत के कौशल से यूक्रेन और गाज़ा के युद्धों को जल्दी खत्म करवा देंगे। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के पांच महीने बाद भी ये दोनों संघर्ष जारी हैं।

नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई बातचीत में गाज़ा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर एक समझौते पर काम करने पर चर्चा हुई। उसी दौरान, इज़राइल के अधिकारी कतर में हमास के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे थे, जिसमें अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। ट्रंप ने बैटक से पहले ही अनुमान जताया था कि इस सप्ताह एक समझौता हो सकता है।

नई दिल्ली, 08 जुलाई। वैश्विक आतंकी वित्तपोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया है कि फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक अमेजन से खरीदे गये थे। एफएटीएफ ने दावा किया कि 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी को पेमेंट पेपल से हुआ था।

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए एफएटीएफ ने कहा कि वित्तीय सहायता के बिना ऐसे हमले संभव नहीं थे। एफएटीएफ ने कहा था कि वह 200 अधिकार क्षेत्रों वाले अपने वैश्विक नेटवर्क द्वारा प्रदान किए गए मामलों को संकलित करते हुए, आतंकवादी वित्तपोषण का व्यापक विश्लेषण करेगा। भारत में आतंकवादी हमले के लिए सामग्री की खरीद के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग की केस स्टडी देते हुए, एफएटीएफ ने कहा कि हमले में इस्तेमाल किए गए तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का एक प्रमुख घटक – एल्यूमीनियम पाउडर – ईपीओम अमेजन से खरीदा गया था। इस सामग्री का उपयोग विस्फोट के प्रभाव को बढ़ा

आतंकी वित्तपोषण की वैश्विक निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया

■ **एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि आतंकवादी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व ऑनलाइन मार्केट प्लेस का दुरुपयोग कर रहे हैं।**

वैश्विक आतंकी वित्तपोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया है कि फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का एक प्रमुख घटक – एल्यूमीनियम पाउडर – ईपीओम अमेजन से खरीदा गया था। इस सामग्री का उपयोग विस्फोट के प्रभाव को बढ़ा

(अर्थोरेटरियनड्रिफ्ट)। अगर संस्थागत मानदंड और कमजोर होते गए, तो अमेरिका एक “सॉफ्ट ऑर्थोरेटरियन” यानी नरम तानाशाही की ओर फिसल सकता है, जहाँ एक पार्टी का वर्चस्व हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो, और असहमति को अपराध मान लिया जाए। जरूरी स्थितियों पहले से मौजूद हैं तथा अब बस इरादे की जरूरत है।

लेकिन, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका का इतिहास लचीलेपन और पुनर्निर्माण का रहा है। सिविल वॉर से लेकर वॉटरगेट तक, अमेरिका ने ऐसे संकटों का सामना किया है, जो अजेय लगते थे। सवाल यह है कि क्या यह देश एक बार फिर अपने आत्मबल से खुद को सुधार संकेगा, इससे पहले कि दरारें टूटन में बदल जाएं।

कुल मिलाकर, अमेरिकी तंत्र के भविष्य को न तो सिर्फ अदालतें तय कर सकती हैं, और न सिर्फ

आतंकी वित्तपोषण की वैश्विक निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया

■ **एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि आतंकवादी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व ऑनलाइन मार्केट प्लेस का दुरुपयोग कर रहे हैं।**

वैश्विक आतंकी वित्तपोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया है कि फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का एक प्रमुख घटक – एल्यूमीनियम पाउडर – ईपीओम अमेजन से खरीदा गया था। इस सामग्री का उपयोग विस्फोट के प्रभाव को बढ़ा

बैलट बॉक्स में। अमेरिकन व्यवस्था का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि क्या इसके नागरिक और नेता दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर उन गहरे मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं, जो इस गणराज्य को एक सूत्र में बाँधते हैं। और वे मूल्य हैं— निष्पक्षता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति साझा प्रतिबद्धता।

अगर ऐसा नहीं हो सका, तो खतरा विदेशी नहीं होगा, वह भीतर से ही आएगा।

इलेक्ट्रिक कारों से लेकर अंतरिक्ष शोध तक के उद्योगों को झकझोर देते वाले अरबपति उद्यमी एलन मस्क अब एक नई दिशा में, अमेरिकन राजनीति में कदम रख चुके हैं। अपनी नई राजनीतिक पार्टी, “अमेरिका पार्टी” की शुरुआत के साथ, मस्क ने लोकतांत्रिक इतिहास की मजबूत प्रहरि, अमेरिकी द्वि-दलीय व्यवस्था की जड़ों को चुनौती देने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने यह कदम ऐसे समय पर उठाया

ट्रंप ने 14 देशों के लिए नए टैरिफ घोषित किए

ट्रंप ने इन सभी 14 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है

- **इन देशों में जापान व दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों के अलावा म्यांमार, बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। कई देश तो ऐसे हैं जो लम्बे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं।**

कारण इन्हें निर्लांबित कर दिया गया था। ट्रंप ने ‘दृथ सोशल प्लेटफॉर्म’ पर जापान और दक्षिण कोरिया को लिखे पत्र में कहा, यदि किसी कारण से आप अपने टैरिफ बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो आप उन्हें जिस भी संख्या में बढ़ाना चाहते हैं, वह हमारे द्वारा लगाए जाने वाले 25 प्रतिशत में जोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि उच्च टैरिफ एक अगस्त से प्रभावी होंगे और विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमीनियम जैसे पहले से घोषित सेक्टर टैरिफ के साथ नहीं जुड़ेंगे।

ट्रंप के पत्रों में जापान और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी गई थी कि उनके टैरिफ में किसी भी वृद्धि के साथ ही अमेरिकी शुल्कों में भी वृद्धि कर दी जाएगी। ट्रंप ने घोषणा की कि इसी तरह के पत्र

12 अन्य देशों के नेताओं को भेजे गए, जिनमें मलेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, लाओस, टय्नीसीया, इंडोनेशिया, बंगलादेश, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कंबोडिया, थाईलैंड शामिल हैं। उन्हें यह सूचना दी गई कि अगले महीने से उन पर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाएंगे। मलेशिया, कजाकिस्तान और टय्नीसीया पर टैरिफ दर 25 प्रतिशत होगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका और बिर्हाना के लिए यह 30 प्रतिशत होगी। इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत और बांग्लादेश एवं सर्बिया पर 35 प्रतिशत टैरिफ दर लागू होगी। कंबोडिया और थाईलैंड पर टैरिफ दर 36 प्रतिशत होगी, जबकि लाओस एवं म्यांमार पर यह 40 प्रतिशत तक होगी।